बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 151

मौद्रिक जोखिम से बचाव

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने विदेशों में रुपये के बाजार के सवाल की जांच परख के लिए जो कार्य बल गठित किया था उसने अपनी रिपोर्ट दे दी है। रुपये के नॉन डिलिवरेबल फॉरवर्ड (एनडीएफ) बाजार में भारी पैमाने पर हो रहा कारोबार रिपोर्ट की दृष्टि से उल्लेखनीय रहा। समिति के मुताबिक उस कारोबार का आकार देश में हो रहे कारोबार से भी कहीं अधिक है। आश्चर्य नहीं कि आरबीआई इस मुद्दे को लेकर चिंतित है। भले ही वह रुपये के लिए कोई खास दायरा या लक्ष्य लेकर नहीं चल रहा हो लेकिन मुद्रा की स्थिरता को बरकरार रखना उसक दायित्वों में से एक है। अगर रुपये का मूल्य काफी हद तक विदेशों में परिचालित एनडीएफ से तय होता है और वह केंद्रीय बैंक के नियमन और उसकी निगरानी से परे है तो इसमें किसी बड़े बदलाव का अनुमान लगाना या प्रबंधन करना दोनों मुश्किल हो जाते हैं। फिलहाल मुद्रा को लेकर कोई बड़ा मसला नहीं है लेकिन वर्ष 2013 में अमेरिकी केंद्रीय बैंक द्वारा की गई टैपरिंग का उदाहरण बताता है कि कैसे आरबीआई के लिए मुद्रा बाजार की अस्थिरता का प्रबंधन कर पाना मुश्किल हो सकता है।

रिपोर्ट का यह कहना सही है कि एनडीएफ बाजारों को प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित करने का कोई तरीका नहीं है। सरकार और केंद्रीय बैंक केवल यह कर सकते हैं कि वे घरेलू नियमन में बदलाव लाएं। आरबीआई की पूर्व डिप्टी गवर्नर उषा थोराट की अध्यक्षता वाली समिति का यह कहना सही है कि ऐसा करते हुए यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि कारोबारियों को एनडीएफ के बाहरी कारोबार के बजाय देश में कारोबार करने के लिए प्रोत्साहन मिले। समिति कहती है कि विदेशी बाजार के आकार और उसकी प्रमुखता तथा सीमापार लेनदेन तथा विदेशी विनिमय बाजार या प्रतिभागियों पर लगने वाले प्रतिबंधों की सीमा के बीच एक किस्म की दुविधा व्याप्त है। इसका सीधा अर्थ यह है कि फिलहाल लेनदेन और प्रतिभागियों पर नियामकीय बोझ बहुत अधिक है और यह अतार्किक तरीके से गठित है जिसे ठीक करने की आवश्यकता है। एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था जिसकी विश्व अर्थव्यवस्था के साथ संबद्धता बढ़ रही हो, उसे मौद्रिक जोखिम की हेजिंग के लिए आधुनिक उपायों की आवश्यकता है। यह समझने की आवश्यकता है कि ग्राहक को जानने और राउंड ट्रिपिंग (ऐसे लेनदेन जिनसे राजस्व बढ़ता दिखता है लेकिन हकीकत में आर्थिक स्थिति में कोई बदलाव नहीं आता) को लेकर नैतिक सवाल उठाने के बजाय इस बात की स्पष्ट समझ होनी चाहिए कि वृहद आर्थिक स्थिरता के लिए देश में कारोबार को किस प्रकार बढ़ावा देने की आवश्यकता है। समिति का सुझाव है कि कम से कम विनिमय वाले एनडीएफ को अल्पावधि में इजाजत दी जाए, हालांकि ओवर द काउंटर अनुबंध फिर भी आदर्श होंगे। निश्चित रूप से हेजिंग का आकार और देश में कारोबार की सुगमता बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि हेजिंग की वैध आवश्यकताओं को विदेशी बाजारों में ले जाया जा सके।

रुपये का अधिक बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करने को लेकर समिति की अनुशंसाएं बेहतर हैं लेकिन बुनियादी जरूरत यह सुनिश्चित करने की है कि वृहद आर्थिक माहौल अपने आप में इतना स्थिर हो कि इन चिंताओं को दूर किया जा सके। अक्सर देश के आंतरिक असंतुलन मसलन उच्च राजकोषीय घाटा और मुद्रास्फीति आदि बाह्य क्षेत्र की समस्या पैदा करते हैं। ऐसे में यह अहम है कि नीति निर्माता वृहद आर्थिक स्थिरता को मजबूत बनाने पर काम करें। मजबूत और स्थिर बुनियाद मुद्रा बाजार में सटोरिया गतिविधि पर रोक लगाएगी। इस संदर्भ में कम राजकोषीय घाटा और सार्वजनिक क्षेत्र की उधारी की आवश्यकता यह सुनिश्चित करेगी कि ऋण के स्थायित्व को लेकर कोई चिंता न हो। निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए वास्तविक सुधार अपनाने से उच्च राजकोषीय घाटे की समस्या हल करने में मदद मिलेगी।

अजय मोहंती

मोदी की यॉर्कर से विचलित पाकिस्तान

कश्मीर मामले में हमेशा पाकिस्तान पहल करता था और भारत प्रतिक्रिया देता था। मोदी ने अनुच्छेद 370 में संशोधन कर हालात बदल दिए हैं।

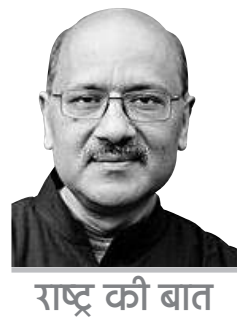

राष्ट्र की बात

शेखर गुप्ता

मुझ पर यह आरोप लग सकता है कि मैं दूसरों के कष्ट में सुख ले रहा हूं लेकिन फिर भी मैं इस बात पर खुश होना चाहता हूं कि पाकिस्तानी नैशनल असेंबली ने गत सप्ताह भारतीय संविधान पर चर्चा करने में अच्छा खासा समय खर्च किया और इसे बखूबी तवज्जो दी।

भारत द्वारा अनुच्छेद 370 और 35 ए को लेकर जो निर्णय लिए गए वे कई वजहों से पाकिस्तान में हलचल की वजह बने। एकतरफा रोमांच इसका कारण नहीं है। सबसे बड़ी वजह तो यही है कि एक ऐसा देश, जिसके शासक अपने संविधान को खारिज करने के लिए जाने जाते रहे हैं, वह भारत के संविधान के लिए इस कदर चिंतित है।

मेरे लिए अहम बात थी इमरान खान का भारत पर शिमला समझौते का उल्लंघन करने का इल्जाम लगाना। मैं पाकिस्तान की राजनीति पर इस कदर नजर रखता हूं मानो वह भारत का आंतरिक मामला हो। मुझे वहां का कोई ऐसा शासक याद नहीं आता जिसने उस दस्तावेज के प्रति निष्ठा जताते हुए शपथ ली जो जिसे वे अक्सर कागज का पुराना और अप्रासंगिक टुकड़ा करार देते हैं। अपने जमाने के सबसे काबिल तेज गेंदबाजों में शामिल रहे इमरान खान ने कुछ ही रोज पहले व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप से कहा था कि भारत और पाकिस्तान 70 वर्ष तक कश्मीर मसले को द्विपक्षीय तरीके से हल करने में नाकाम रहे और अब दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति होने के नाते उन्हें मध्यस्थता करनी चाहिए।

बीते 31 वर्षों में दोनों देशों के बीच तीन द्विपक्षीय समझौते हुए। सन 1972 में शिमला समझौता, सन 1999 में लाहौर समझौता और 2004 में इस्लामाबाद समझौता। ये सारे महज खानापूरी बनकर रह गए। तमाम अन्य बातों के अलावा तीनों समझौतों की एक केंद्रीय बात है, कश्मीर समेत सभी मुद्दों को द्विपक्षीय तरीके से हल करना।

अन्य पाकिस्तानी नेताओं ने भी इस प्रतिबद्धता को आराम से तोड़ा। परंतु जुल्फिकार अली भुट्टो द्वारा शिमला समझौते पर हस्ताक्षर के बाद पाकिस्तान में जो भी शासनाध्यक्ष हुए, वे चाहे चुनाव जीते हों, दोबारा चुने गए हों या सेना की मदद से गद्दीनशीं हुए हों, किसी ने भी खुलकर समझौते को खारिज नहीं किया। इसे मानने का ढोंग जारी रखा गया।

लाहौर और इस्लामाबाद घोषणापत्र शिमला समझौते की प्रतिबद्धता दोहराते हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से कश्मीर मसले पर मध्यस्थता का आग्रह कर इमरान खान पहले ऐसे पाकिस्तानी नेता बन गए हैं जिसने पहले के तीनों समझौतों को औपचारिक रूप से नकार दिया है। अब वह भारत पर इसके उल्लंघन का इल्जाम लगा रहे हैं। यह नौ सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली का सटीक उदाहरण है। यहां अहम बात यह है कि कश्मीर को लेकर मूलभूत सामरिक और राजनीतिक समीकरण उलट चुके हैं। सन 1947 से अब तक पाकिस्तान पहल करता था। सन 1947 में लूट और बलात्कार करने वाले कबाइली लुटेरों को भेजने से लेकर ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत फौजियों को मुफ्ती बनाकर भेजने और अगस्त-सितंबर 1965 में ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम में कश्मीर में टैंक भेजने तक वह ऐसा करता रहा। सन 1972 में शिमला समझौता होने तक कश्मीर में पहला कदम पाकिस्तान उठाता रहा।

इसके बाद 17 वर्ष शांति रही लेकिन पाकिस्तान आगे की तैयारी में लगा रहा। वह परमाणु प्रतिरोध तैयार करता रहा, उसने अफगानिस्तान में अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन की तत्कालीन सोवियत संघ के खिलाफ लड़ाई में सहायता की। सन 1989 तक उसने परमाणु हथियार तैयार कर लिए। पश्चिम में एक जिहाद जीता गया और पाकिस्तान ने पूर्व में दूसरे की तैयारी शुरू कर दी। उसके बाद करगिल, आईसी-814 के अपहरण, भारतीय संसद पर हमला, मुंबई पर हमला, पठानकोट, पुलवामा जैसी घटनाएं हुईं। पाकिस्तान ने हर बार पहला वार किया और भारत प्रतिक्रिया तलाशता रह गया। भारत के हालिया कदम को लेकर हम एक अलग पहलू पर चर्चा करेंगे। परंतु हमें यह भी मानना होगा कि 70 वर्ष तक भारत ने यथास्थिति कायम रखी जबकि ताकत और आकार में वह काफी बड़ा है। जबकि पाकिस्तान लगातार इसे बदलने में लगा रहा। पिछले दिनों भारत ने इसे बदल दिया। अब पाकिस्तान प्रतिक्रिया के लिए छटपटा रहा है क्योंकि उसके रणनीतिकार ऐसी प्रतिक्रिया के लिए तैयार ही नहीं किए गए। इमरान खान द्वारा वॉशिंगटन में शिमला, लाहौर और इस्लामाबाद समझौतों को नकारने के एक सप्ताह बाद नरेंद्र मोदी ने इसका विरोध न कर एक नई इबारत लिखी। उन्होंने नाटकीय रूप से इससे सहमति जता दी। अगर उन समझौतों से पाकिस्तान तथा विश्व बिरादरी को लग रहा था कि कश्मीर की अंतिम स्थिति पर अभी बहस और मोलतोल संभव है तो वह भ्रम अब समाप्त हो चुका है। इमरान सही थे, वे समझौते भी अब समाप्त हैं। अब पाकिस्तान को उकसाने, इनकार करने, मदद की पेशकश, बातचीत, आदि के अपने मानक व्यवहार से अलग तरीका तलाशना होगा। अतीत में भारत बड़ी शक्तियों से आग्रह करता था कि वे पाकिस्तान पर दबाव बनाएं। अब वह काम पाकिस्तान कर रहा है।

अब उसे अपनी सीमा और घटते कद का अहसास हो चुका है और वह 6 अरब डॉलर की राशि के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के समक्ष गिड़गिड़ा रहा है। इसे ऐसे समझें कि इससे अधिक राशि तो आर्सेलरमित्तल दिवालिया एस्सार स्टील को खरीदने के लिए चुका रही है। पाकिस्तान की राजनीति, संस्थान और समाज सभी भंगुर अवस्था में हैं। यह बलूचिस्तान को संभाल सकता है लेकिन पख्तूनों का शांतिपूर्ण आंदोलन जोर पकड़ चुका है। उसके पास एक लाभ है, वह अफगानिस्तान का स्थानीय संरक्षक बनकर ट्रंप की वहां बने रहने का दिखावा करते हुए वहां से निकलने मे मदद कर सकता है। परंतु इसकी उसे बड़ी कीमत चुकानी होगी। अगर पाकिस्तान को कश्मीर में अच्छा प्रदर्शन करना है तो वह कश्मीर में नहीं उलझ सकता। अभी तो कतई नहीं क्योंकि आतंक के खिलाफ उसकी प्रतिबद्धता को लेकर वित्तीय कार्यबल की तय मियाद कुछ सप्ताह में समाप्त हो रही है। इमरान खान मानसिक रूप से इसके लिए तैयार नहीं थे, यह उनकी क्षमता से भी परे था। हमें यह भी मानना होगा कि सारे फैसले वह नहीं लेते, इसमें सैन्य मुख्यालय की भूमिका रहती है। वे दोनों मोर्चों पर पहल चाहते हैं। पूर्व पाकिस्तानी राजनयिक हुसैन हक्कानी ने द प्रिंट के लिए लिखे एक आलेख में एक पंक्ति लिखी थी जिसे मैं भी लिखना चाहता। उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान की नीति हमेशा कश्मीर मुद्दे का अंतरराष्ट्रीयकरण करने की रही जबकि भारत उसे द्विपक्षीय रखना चाहता था। मोदी सरकार ने अब कश्मीर को भारत और पाकिस्तान का आंतरिक मसला बना दिया।भारत में इस विषय को लेकर मोदी समर्थकों और राजनीतिक एवं बौद्धिक अल्पमत वालों के बीच बहस चल रही है जो इसे अलोकतांत्रिक मानते हैं। पाकिस्तान में चर्चा है कि ऐसा कैसे हो गया और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को इसकी भनक कैसे नहीं लगी। कोई बिक तो नहीं गया? अब क्या किया जाए? नैशनल असेंबली में इमरान के गुस्से में यह बात नजर आई। उन्होंने वहां कहा कि उनसे क्या अपेक्षा की जा रही है? कि वह भारत पर हमला कर दें? मेरा यह तात्पर्य नहीं है कि भारत में सब ठीक है या कश्मीर में ताजा पहल एकदम सही है। बात यह है कि आज पाकिस्तान जहां है वहां यह प्रासंगिक नहीं है। वह अनुच्छेद 370 पर दुख जताने का जितना ढोंग कर रहा है, प्रमुख कश्मीरी नेताओं को जिन्हें वह दलाल कहता है, उनको बंदी बनाए जाने की जितनी तारीफ करे और भारतीय कश्मीर में नागरिक अधिकारों को लेकर वह चाहे जितना चीखे, वह उतना ही अधिक मूर्खतापूर्ण नजर आता है।

वह अलगाववादियों को पकड़े जाने का विरोध करता है जबकि उसने दो प्रधानमंत्रियों नवाज शरीफ और शाहिद खकान अब्बासी और एक पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को जेल में डाला और एक अन्य परवेज मुशर्रफ को निर्वासित किया है। अब नवाज शरीफ की बेटी और विपक्षी नेता मरयम नवाज भी जेल में हैं। इसी तरह पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री राणा सनाउल्ला, नवाज की पार्टी के तीन सांसद, दो पख्तून सांसद आदि भी बंदी बनाए गए। नवाज को छोड़कर इनमें से किसी को सजा नहीं हुई है। इनमें से ज्यादातर बिना किसी जांच के महीनों से जेल में बंद हैं। यह पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। यथास्थिति बदल चुकी है। या तो पाकिस्तान इसे स्वीकार करे या कुछ मनमानी करे। या वह प्रार्थना करे कि घाटी में हालात एक बार फिर बेकाबू हो जाएं और हालात इतने बिगड़ जाएं कि भारतीय फौज आपा खो दे। अब यही उसकी आखिरी उम्मीद है।

जम्मू कश्मीर में निवेशक सम्मेलन कहीं जल्दबाजी में उत्साह तो नहीं!

जिंदगीनामा

कनिका दत्ता

भारतीय कंपनी जगत जम्मू कश्मीर से संबंधित मामले में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जबरदस्त तत्परता से तालमेल बिठाने की कोशिश में लगा हुआ है। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) इस साल अक्टूबर में जम्मू कश्मीर के लिए केंद्रित पहला निवेशक सम्मेलन आयोजित करने जा रहा है। क्या यह असंगत उत्साह है या गलत आशावाद है? शायद अपरिपक्व उत्साह इस सम्मेलन को कहीं बेहतर तरीके से व्याख्यायित कर सकता है।

जम्मू कश्मीर में कारोबारी संभावनाओं को लेकर सीआईआई ने एक बड़ी तस्वीर पेश की है। यह देखने में काफी मोहक लग रहा है। अनुच्छेद 370 लागू रहने के दौरान राज्य में जमीन एवं कामगारों की उपलब्धता जैसे मुद्दे कारोबारी गतिविधियों के बड़े अवरोधक थे। लेकिन बदले हुए हालात में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां, छोटे एवं मझोले स्तर की विनिर्माण इकाइयां और पर्यटन को बढ़ावा मिलने से यहां बेरोजगारी की अधिकता एवं निम्न विकास से मुकाबला करने में मदद मिलेगी। एक राज्य के तौर पर जम्मू कश्मीर में कारोबारी सुगमता की अंदरूनी स्थिति तमाम वजहों से ठीक नहीं है। लेकिन इसने आश्चर्यजनक तौर पर मानव विकास सूचकांक में पश्चिम बंगाल और राजस्थान जैसे नौ अन्य राज्यों को पीछे छोड़ा था। इससे पता चलता है कि यहां पर एक हद तक शिक्षित एवं स्वस्थ लोग मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है।

फिर भी उद्योग जगत के लिए 'देखने एवं इंतजार करने' की रणनीति पर चलने के कई बाध्यकारी कारक हैं। ऐसे में अचरज की बात नहीं है कि जम्मू कश्मीर में कारोबारी योजनाओं के बारे में पूछे जाने पर अधिकतर उद्यमी इसी के पक्षधर नजर आए। जम्मू कश्मीर में निवेशक सम्मेलन का आयोजन राजनीतिक नजरिये से एक बेहतर तस्वीर पेश करने का माध्यम बन सकता है लेकिन इस तरह के सम्मेलनों की अहमियत व्यावहारिक स्तर पर संदिग्ध ही रही है। एक दशक से अधिक समय से ऐसे सम्मेलन शोहरत दिलाने का जरिया साबित होते रहे हैं। मोदी ने ही गुजरात का मुख्यमंत्री रहते समय यह सिलसिला शुरू किया था। यह अलग बात है कि कोई भी राज्य उन निवेशक सम्मेलन में होने वाले तमाशे की बराबरी नहीं कर पाया है।

गुजरात सरकार के निवेशक सम्मेलनों ने एक परिपाटी तय कर दी। बड़े पैमाने पर निवेश की मंशा रखने वाले संभावित निवेशकों को इस सम्मेलन में बुलाया जाता है और पूरे तामझाम से होने वाले सम्मेलन में आए मेहमानों को उस राज्य के मुख्यमंत्री एवं आला अफसर वहां निवेश से जुड़े लाभों (अक्सर आभासी) के बारे में बताते हैं। इसमें निवेश पर मिलने वाले कर अवकाश और जमीन अधिग्रहण एवं श्रम संबंधी मसलों के त्वरित समाधान जैसे आश्वासन शामिल होते हैं। भारत में ये समस्याएं अमूमन हरेक राज्य में विनिर्माण को बाधित करती हैं।

उसके बाद कुछ दिग्गज उद्योगपति उस राज्य से जुड़ी खासियत (यह भी अक्सर आभासी ही होती हैं) के बारे में भाषण देने आते हैं। गुजरात और पश्चिम बंगाल के निवेशक सम्मेलनों में मुकेश अंबानी भी जाते हैं। इस दौरान कारोबारी जमात एवं नौकरशाही के बीच अनौपचारिक बातचीत भी होती है। अंत में, उस राज्य का जनसंपर्क विभाग हरकत में आता है और निवेश की प्रतिबद्धता से जुड़े वादों (कथित तौर पर सहमति पत्र) का आंकड़ा जारी कर देता है जो अक्सर हजारों करोड़ रुपये का होता है। लेकिन उनमें से बहुत कम वादे ही जमीन पर साकार रूप ले पाते हैं।

मुमकिव है कि जम्मू कश्मीर निवेशक सम्मेलनों से जुड़ी इस प्रवृत्ति को बदल दे और वहां पर निवेश की योजना को लेकर वाकई गंभीर कारोबारियों की लंबी कतार लग जाए। अगर वे अपनी घोषणाओं के साथ जम्मू कश्मीर में पैसा लगाने को भी तैयार हो जाते हैं तो देश के इस सबसे नए केंद्रशासित प्रदेश को विकास का स्वर्ग बनाया जा सकता है। अगर वाकई में ऐसा होता है तो कश्मीर घाटी में फिलहाल कर्फ्यू जैसे हालात में रहने के लिए मजबूर लोगों समेत हरेक भारतीय इस पर खुश होगा। समस्या यह है कि एक संवैधानिक प्रावधान को हटाकर हो सकता है कि एक ऐतिहासिक भूल सुधार ली गई हो, लेकिन इससे जमीनी स्तर पर भी हालात में बदलाव आना दूसरी बात है। जम्मू कश्मीर का विकास के मामले में पीछे रह जाने का वहां पर भूमि स्वामित्व एवं रोजगार जैसी बंदिशों से खास लेना-देना नहीं है। इसका अधिक संबंध इस बात से है कि केंद्र एवं राज्य के नेतृत्व ने पाकिस्तान के साथ रिश्तों को इतने खराब ढंग से संभाला कि जम्मू कश्मीर स्थायी अशांति की स्थिति में रहने के लिए अभिशप्त हो गया। निकट भविष्य में तो इन बाह्य कारकों में किसी भी तरह के बदलाव की संभावना कम ही है।

निवेश के लिए राजनीतिक एवं सामाजिक स्थायित्व जरूरी होने से केंद्र को जम्मू कश्मीर में निवेश करने जा रहे लोगों को सुरक्षाबलों की भारी मौजूदगी से इतर चीजों का भी ऐलान करना होगा। कारोबारी सुगमता के लिए भारी पुलिसबल इकलौती गारंटी नहीं होता है। लगातार घेराबंदी की स्थिति में रहते हुए भी आर्थिक चमत्कार करने में सफल इजरायल को अक्सर एक मिसाल के तौर पर पेश किया जाता है। लेकिन भारत अगर अपने अल्पसंख्यकों का भी एकीकरण करने को लेकर गंभीर है तो वह इजरायल मॉडल को शायद ही अपनाना चाहेगा। पाकिस्तान एवं चीन की क्षेत्रीय आकांक्षाओं का सामना करने के लिए एक तरह की सुविचारित योजना भी इस कवायद का एक अहम हिस्सा है। अभी यह नजर नहीं आ रही है।

इस बात की संभावना कम ही है कि अक्टूबर के खुशनुमा वक्त में होने वाले इस निवेशक सम्मेलन में शिरकत करने जा रहे उद्योगपतियों को इस बाधा के बारे में पता ही नहीं होगा। कोई बात नहीं, कम-से-कम दो दिनों के लिए तो कश्मीर घाटी में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

कानाफूसी

कौन बनेगा तेलंगाना भाजपा प्रमुख?

जिस तरह कांग्रेस पार्टी दिल्ली इकाई के लिए अध्यक्ष तलाशने में लगी हुई है, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना इकाई के लिए अध्यक्ष की खोज में जुटी हुई है। भाजपा अगले चुनाव के पहले तेलंगाना में मजबूत राजनीतिक उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है। कांग्रेस के पराभव और सत्ताधारी तेलंगाना राष्ट्र समिति के खिलाफ बनते माहौल के बीच पार्टी को लग रहा है कि वह लाभ उठा सकती है। गत मई में संपन्न लोकसभा चुनाव में पार्टी को चार सीटों पर जीत हासिल हुई थी और महज पांच महीनों के अंतराल में पार्टी का मत प्रतिशत 7 फीसदी से बढ़कर 19 फीसदी हो गया। भाजपा ने सिकंदराबाद के सांसद कृष्ण रेड्डी को केंद्र में गृह राज्य मंत्री भी बनाया है। जाहिर है यह कदम पार्टी के विकास को ध्यान में रखकर उठाया गया है। भाजपा के मौजूदा प्रदेश प्रमुख डॉ. के लक्ष्मण पार्टी के वरिष्ठ ओबीसी नेता हैं और लोग उनकी इज्जत करते हैं लेकिन वह दिसंबर के विधानसभा चुनाव में मुशीराबाद सीट से चुनाव हार गए। वह अन्य दलों के नेताओं को भी पार्टी में नहीं ला सके। इन हालात में मुरलीधर राव का नाम चर्चा में है। राव पहले विद्यार्थी परिषद में रहे और बाद में स्वदेशी जागरण मंच से जुड़ गए। उन्होंने कई बार लोकसभा चुनाव लड़ने का प्रयास किया लेकिन सीएच विद्यासागर राव ने उनकी राह रोक दी। निजामाबाद के सांसद अरविंद धर्मपुरी ने सार्वजनिक रूप से उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाने की मांग की है।

आपका पक्ष

कुपोषण मुक्त होगा छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य को कुपोषण मुक्त करने के लिए गांधी जयंती (2 अक्टूबर) से कुपोषण और एनीमिया पीड़ितों को प्रतिदिन निःशुल्क पौष्टिक भोजन देने की घोषणा की है। यह अभियान महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर आरंभ किया जाएगा। सरकार ने अगले तीन साल में राज्य को कुपोषण मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। कुपोषण से लड़ने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने ठोस कदम उठाया है। देश के दूसरे राज्यों में भी कुपोषण हटाने के लिए कई योजनाएं चल रही हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ पिछड़ा राज्य है तथा यहां गरीबी भुखमरी दूसरे राज्यों से अधिक है। वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड तथा झारखंड इन तीन राज्यों का गठन हुआ था। आज तीनों राज्यों में उत्तराखंड की स्थिति कुछ ठीक है। झारखंड तथा छत्तीसगढ़ का विकास धीमी गति से हुआ है। केंद्र सरकार ने भी कुपोषण खत्म करने की दिशा में

पहल की है। लेकिन केंद्रीय योजनाएं राज्यों तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती है। केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन की गति राज्यों में धीमी पड़ जाती है जिससे लोगों को इसका समुचित लाभ नहीं मिल पाता है। छत्तीसगढ़ तथा झारखंड खनिज संपन्न राज्य होते हुए भी उपेक्षा के शिकार हैं। यहां बेरोजगारी, भुखमरी तथा गरीबी

कुपोषण मुक्त करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार निःशुल्क पौष्टिक भोजन देगी

अधिक है। सरकार को कुपोषण मुक्त करने के लिए निःशुल्क पौष्टिक भोजन देने के बजाय वह दो वक्त पौष्टिक भोजन कर सके इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। राज्य अपने नागरिकों को उनकी क्षमता के अनुसार रोजगार प्रदान कर सकता है। ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी जरूरी नहीं बल्कि सरकार उसे किसी निजी कंपनियों या संस्थाओं में रोजगार प्रदान करने में मदद कर सकती है जिससे वह कमा सके तथा खुद भोजन प्राप्त कर सके।

सुचरिता साहू, रायपुर

कश्मीर-लद्दाख में अब विकास की बारी

जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के कुछ प्रावधान हटाने और जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने से अब यहां विकास संभव हो सकेगा। रोजाना मीडिया में जम्मू कश्मीर की खबरें आ रही हैं कि वहां धारा 144 लगाया गया है। वहां बड़ी कड़ाई बरती जा रही है। ऐसा इसलिए शायद आतंकी गतिविधि वहां अधिक है। लेकिन इन सब के बीच लद्दाख की खबरें नहीं मिल पा रही है। कश्मीर में पर्यटन स्थल होने तथा फलों की खेती के कारण वहां का विकास जल्द संभव है। लेकिन लद्दाख के विकास में सरकार को काफी कवायद करनी पड़ेगी। लद्दाख में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां घास का एक तिनका भी नहीं उगता है। बर्फ से ढंके लद्दाख में पर्यटक भी काफी कम जाते हैं। हालांकि लद्दाख भारत का ऊर्जा का बड़ा स्रोत बन सकता है। यहां सौर ऊर्जा की अधिक संभावनाएं हैं। इसके अलावा जल विद्युत की भी अपार संभावनाएं हैं। सरकार को पहले इन जगहों में जाने के लिए अच्छी सड़कों का निर्माण करना होगा। अगर इन जगहों में जाना सुलभ होगा तो लोग वहां जाएंगे और वहां का विकास तेज गति होगा। कश्मीर को भारत का स्वर्ग कहा जाता है। लेकिन आतंकवादी गतिविधियों तथा अनुच्छेद 370 के कारण वह उपेक्षा का शिकार था। अब केंद्र शासित प्रदेश बनने से विकास संभव होगा।

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।